



WRITERS CREW INTERNATIONAL RESEARCH

JOURNAL

विद्यालयी शिक्षा में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका: उत्तराखंड में

हंस फाउंडेशन के कार्यक्रमों का मूल्यांकन

डॉ. मीनाक्षी वर्मा

प्रोफ़ेसर

शिक्षा संकाय

हिमगिरी ज़ी यूनिवर्सिटी

&

संतोष सिंह नेगी

शोध छात्र

शिक्षा और मानविकी स्कूल

हिमगिरी ज़ी यूनिवर्सिटी

देहरादून



सारांश

शिक्षा अंधकार से प्रकाश की ओर एक आंदोलन है। शिक्षा के बिना लोग गरीबी और पिछड़ेपन के अंतर-पीढ़ीगत चक्र में फंस जाते हैं। भारत के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना राज्य और केंद्र दोनों सरकारों की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। और इस प्रकार, भारत सरकार के विभिन्न विभाग अक्सर अधिक से अधिक बच्चों को अपनी शिक्षा पहल के दायरे में लाने के लिए दान का समर्थन करते हैं। शिक्षा किसी भी व्यक्ति का एक प्राकृतिक अधिकार है और सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है, इसलिए, वित्तीय स्थिति में व्यापार का एक लेख है, लेकिन यह अन्य सेवाओं से भिन्न है क्योंकि यह एक सामुदायिक विशेषता है। शिक्षा निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में सीखने और उच्च शिक्षा के मामले में लाभ देती है, इससे समाज को सामाजिक तरीकों से लाभ होता है जिससे एक किसान साक्षर कौशल के माध्यम से अधिक रचनात्मक बन सकता है, साथ ही एक साक्षर महिला अपने परिवार की स्वास्थ्य आवश्यकताओं की अच्छी देखभाल करने में सक्षम हो सकती है, अंत में एक शिक्षित व्यक्ति एक बेहतर नागरिक के रूप में सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों का



5410online

प्रयोग कर सकता है। इसलिए सरकार के लिए शिक्षा में निवेश करना आवश्यक है क्योंकि इससे प्रगतिशील बाहरी प्रभाव मिलते हैं। यह शोधपत्र शिक्षा क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका का पता लगाने का प्रयास करता है। शिक्षा

जो चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक है, जिससे मानव व्यक्तित्व की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संस्कृति सामने आती है। एनजीओ जागरूकता पैदा करते हैं और भविष्य में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। कुछ एनजीओ के पीछे मानव मस्तिष्क पर प्रकाश डाला गया है।

मुख्य शब्द: एनजीओ, भूमिका, संगठन, शिक्षा प्रणाली, सरकार।

प्रस्तावना

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी: पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) विकास का नवीनतम मंत्र रहा है। यह विकास रणनीतियों में एक प्रसिद्ध नारा भी बन गया है, खासकर पिछले कुछ दशकों में कई विकासशील और उन्नत देशों में।

हालांकि सार्वजनिक-निजी भागीदारी का चलन बिलकुल नया नहीं है, लेकिन नव-उदारवादी युग में यह लोकप्रिय हो गया है, एक तरफ इसने बहुत बड़ा आकार ले लिया है, ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश



5410online

किया है जो अब तक सार्वजनिक एकाधिकार के लिए आरक्षित थे, और दूसरी तरफ इसने अलग-अलग रूप ले लिए हैं जो हाल ही तक अज्ञात थे। यहां तक कि वे देश भी सार्वजनिक-निजी भागीदारी के विचार के प्रति ग्रहणशील हो गए हैं और यहां तक कि अधिकांश विकास गतिविधियों में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। सार्वजनिक-निजी भागीदारी को कई अर्थव्यवस्थाओं में विभिन्न बुनियादी ढांचे के विकास क्षेत्रों जैसे हवाई अड्डों, रेलवे, सड़कों आदि के विकास में अपनाया जा रहा है। लेकिन यह अब इन क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है। इसने उन क्षेत्रों में भी प्रवेश किया है जो कई दशकों या सदियों से सार्वजनिक एकाधिकार के क्षेत्र थे। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो लंबे समय से राज्य के विशेष अधिकार क्षेत्र तक ही सीमित था। लेकिन सार्वजनिक-निजी भागीदारी को शिक्षा तक बढ़ाया जा रहा है, जिसमें प्राथमिक शिक्षा भी शामिल है, जिसे सार्वभौमिक मानव/मौलिक अधिकार माना जाता है, और साथ ही स्वास्थ्य जैसे अन्य मानव विकास क्षेत्र और यहां तक कि गरीबी उन्मूलन से संबंधित गतिविधियों तक भी।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी क्या है?



541Online

सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता का उपयोग करके अपनी आबादी को गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक दृष्टिकोण है। यह एक संविदात्मक व्यवस्था है जिसके माध्यम से एक निजी पक्ष सरकार के सेवा वितरण कार्यों का हिस्सा करता है जबकि संबंधित जोखिम उठाता है। बदले में, निजी पक्ष को पूर्व-निर्धारित प्रदर्शन मानदंडों के अनुसार सरकार से शुल्क प्राप्त होता है। ऐसा भुगतान उपयोगकर्ता शुल्क या सरकारी बजट या दोनों के संयोजन से हो सकता है। विश्व आर्थिक मंच सार्वजनिक निजी भागीदारी को विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न अभिनेताओं के बीच एक स्वैच्छिक गठबंधन के रूप में परिभाषित करता है, जहां दोनों एक सामान्य लक्ष्य तक पहुंचने या साझा जिम्मेदारियों, साधनों, दक्षताओं और जोखिमों को शामिल करने वाली एक विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक साथ काम करने के लिए सहमत होते हैं ¹। जिसमें शिक्षा में सरकार और निजी क्षेत्रों की एक साथ भागीदारी होती है, जिसमें लागत और लाभ और जोखिम और पुरस्कार साझा करने की समझ होती है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत, सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियाँ (केंद्रीय, राज्य या स्थानीय) निजी क्षेत्र की संस्थाओं (कंपनियाँ, फ़ाउंडेशन, गैर-सरकारी संगठन, शैक्षणिक संस्थान या नागरिक) के साथ जुड़ती हैं और एक



541Online

साझा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 'व्यावसायिक' संबंध बनाती हैं जो व्यक्तिगत भागीदारों के उद्देश्यों को भी प्राप्त करता है। दोनों पक्ष एक कार्यक्रम को लागू करने में एक साथ काम करने के लिए सहमत होते हैं, और प्रत्येक पक्ष की स्पष्ट भूमिका होती है और यह कहना होता है कि कार्यान्वयन कैसे होता है।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी कैसे काम करता है?

विभिन्न संदर्भों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के कई मॉडल प्रचलित हैं। हालांकि कई में सामान्य विशेषताएं हैं, लेकिन उनके बीच अंतर भी हैं। व्यापक रूप से प्रचलित मॉडल के अनुसार, सरकार पहल कर सकती है और किसी विशिष्ट परियोजना के माध्यम से शिक्षा के विकास की दिशा में अपने प्रयासों में निजी क्षेत्र को शामिल होने के लिए आमंत्रित कर सकती है; या निजी क्षेत्र ऐसी पहल कर सकता है और सरकार को संचालन की एक नई पद्धति को स्वीकार करने के लिए राजी या मजबूर कर सकता है जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार संयुक्त रूप से कोई सेवा/गतिविधि प्रदान करते हैं। किसी भी मामले में, राज्य और निजी क्षेत्र एक विशिष्ट कार्य के लिए एक साथ आते हैं। आम तौर पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी के विभिन्न मॉडलों में



541Online

सरकार और निजी क्षेत्र के बीच शिक्षा में कुछ विशिष्ट पूर्व-निर्धारित गतिविधियों को करने के लिए एक औपचारिक अनुबंध शामिल होता है, जैसे कि नए संस्थान स्थापित करना और/या संस्थानों को चलाना या शिक्षा में कोई विशेष गतिविधि करना - सभी को राज्य द्वारा और/या स्व-निर्मित संसाधनों के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी का एक विशिष्ट मॉडल निजी क्षेत्र द्वारा बुनियादी ढांचा और सेवा वितरण प्रदान करने का तात्पर्य है; यह डिजाइनिंग, वित्तपोषण, निर्माण और 'संचालन' के लिए भी जिम्मेदार हो सकता है; और यह सरकारों से एकमुश्त/वार्षिक भुगतान और उपयोगकर्ता शुल्क के माध्यम से अपने निवेश की वसूली करता है। सामान्य मॉडल के तहत, यह राज्य के साथ जोखिम साझा करता है।

भारत में शिक्षा में सार्वजनिक-निजी भागीदारी

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में भारतीय शिक्षा के विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में प्रस्तावित किया गया था। माध्यमिक शिक्षा के मामले में एक स्पष्ट और अलग मॉडल तैयार किया गया था। ग्यारहवीं योजना में माध्यमिक शिक्षा में 6,000 नए मॉडल स्कूल स्थापित करने का प्रस्ताव था, जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से



5410online

संबद्ध होंगे, जिनमें से 2,500 स्कूल सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत स्थापित किए जाने थे। घोषित इरादा इन स्कूलों को पिछड़े क्षेत्रों और दूरदराज के क्षेत्रों में स्थापित करना है, जहां अच्छी स्कूली शिक्षा सुविधाएं मौजूद नहीं हैं, ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध हो सके। योजना आयोग द्वारा निजी क्षेत्र के परामर्श से अंतिम रूप दिए गए मॉडल के अनुसार, इन स्कूलों में देश के सर्वश्रेष्ठ निजी स्कूलों में उपलब्ध सर्वोत्तम बुनियादी ढांचा होगा, जिसमें 65 लाख छात्र शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, जिनमें से 25 लाख छात्र समाज के वंचित तबके से होंगे। प्रत्येक स्कूल में लगभग 2,500 छात्र होंगे, जिनमें से 1,000 समाज के वंचित वर्गों से होंगे, जिनसे सांकेतिक शुल्क लिया जाएगा। इन 1,000 छात्रों में से 50 प्रतिशत समाज के सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों से होंगे। इन छात्रों को प्रति व्यक्ति 25 रुपये मासिक शुल्क देना होगा। शेष 50 प्रतिशत बच्चे, जो समाज के अन्य वंचित वर्गों - गैर-आयकर देने वाले परिवारों से होंगे, को प्रति व्यक्ति 50 रुपये प्रति माह का शुल्क देना होगा। इन छात्रों की शेष लागत, जो अनुमानित 1,000-1,200 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह है, केंद्र सरकार द्वारा स्कूलों को प्रतिपूर्ति की जाएगी। अनुमान है कि सरकार को 1,000-1,200 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह का भुगतान करना होगा। 2017 तक



541Online

10,500 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध है, जो सामान्य रूप से बढ़ती कीमतों और विशेष रूप से शिक्षा की बढ़ती लागत के साथ बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा, स्कूलों को विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के तहत संघ और राज्य सरकारों से प्रासंगिक निधियों तक पहुंच मिलती है। स्कूल शेष 1,500 प्रवेशों में से किसी एक को भी प्रवेश देने और किसी भी राशि का शुल्क लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। हालाँकि, यह योजना आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि यह निजी क्षेत्रों के लिए आकर्षक नहीं पाई गई।

उच्च तकनीकी शिक्षा के संबंध में एक और प्रस्ताव पहले भी था, हालांकि इसे औपचारिक रूप से सार्वजनिक-निजी भागीदारी के मॉडल के रूप में वर्णित नहीं किया गया था। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई 1994) द्वारा गठित एक समिति ने छात्रों और निजी संस्थानों को ऋण देने के लिए भारतीय शैक्षिक विकास बैंक की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। बैंक को सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड में स्थापित किया जाना था, जिसमें 3,000 करोड़ रुपये का एक कोष था, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र का योगदान था। जबकि कई



541Online

अन्य सुझावों को लागू किया गया था, यह आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि निजी क्षेत्र कोष में आवश्यक योगदान देने के लिए तैयार नहीं था।

शोध का महत्व

- सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी के महत्व को समझना आवश्यक है।
- उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों में स्कूलों के बुनियादी ढांचे और शिक्षा के स्तर में असमानता की स्थिति को जानना।
- पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में जो सुधार हो रहे हैं, उनकी प्रभावशीलता और दीर्घकालिक परिणामों का अध्ययन आवश्यक है।
- हंस फाउंडेशन द्वारा किए गए कार्यों के प्रभाव का विश्लेषण करने से अन्य शैक्षिक संगठनों और सरकारों को मार्गदर्शन मिलेगा।

विद्यालयी शिक्षा में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका



5410online

• एनजीओ समाज के सबसे कमज़ोर तबके तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। जबकि ज़्यादातर सरकारी पहल शिक्षा की आपूर्ति के लिए रही हैं, कई एनजीओ ने समुदायों के साथ मिलकर काम करने और शिक्षा की माँग को बेहतर बनाने के प्रयास किए हैं।

• इस देश में बड़ी संख्या में बच्चे प्राथमिक विद्यालय पूरा नहीं कर पाते और स्कूल जाने की लागत के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं। कई बच्चे स्कूल जाने के बजाय अपने परिवार के लिए काम करना पसंद करते हैं। नतीजतन, कुछ ही माध्यमिक विद्यालय से बाहर निकल पाते हैं और बहुत कम उच्च शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं। सरकार निरक्षरता से लड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन सिस्टम में मौजूद अड़चनें इस प्रक्रिया को काफी हद तक अक्षम बना देती हैं।

यहां सामाजिक संगठन और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की भूमिका आती है। शिक्षा के क्षेत्र में एनजीओ द्वारा कवर किए जाने वाले कुछ क्षेत्र इस प्रकार हैं:

• एनजीओ उन बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकते हैं, जिन्हें पैसे की कमी के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, उन्हें अपने खर्च पर मुफ्त शिक्षा देकर।



541Online

• गैर सरकारी संगठन उन बच्चों तक पहुँच सकते हैं जो दुर्गमता के कारण स्कूल नहीं जा सकते हैं

और उन्हें उनके घरों में पढ़ा सकते हैं।

• गैर सरकारी संगठन बच्चों की उच्च शिक्षा में भी सहायता करते हैं और उन्हें कौशल आधारित

शिक्षा प्रदान करने की दिशा में काम करते हैं।

• गैर सरकारी संगठन लोगों के बीच जागरूकता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर

स्वास्थ्य, बीमारियों, चिकित्सा के क्षेत्र में।

हंस फाउंडेशन का परिचय

2009 में स्थापित, हंस फाउंडेशन (THF), एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है, जो बच्चों, महिलाओं

और विकलांग व्यक्तियों जैसे हाशिए पर पड़े और वंचित समूहों के स्वास्थ्य और कल्याण की

दिशा में काम करता है। एक समतापूर्ण समाज बनाने के उद्देश्य से, THF उन समुदायों की समग्र

शिक्षा और आजीविका विकास पर भी ध्यान केंद्रित करता है, जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं।



541Online

2009 में स्थापित हंस फाउंडेशन एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है जो भारत में गैर-लाभकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। संगठन के हस्तक्षेप के मुख्य क्षेत्र हैं; शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और विकलांगता। THF की रणनीतिक योजना गरीबी उन्मूलन, आर्थिक असमानताओं और सामाजिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता पर 360° प्रभाव के प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने के उद्देश्य से अपने काम के प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती है।

हंस फाउंडेशन का विचार

एक दशक तक चलने वाली यात्रा की शुरुआत एक ही नाम से हुई - हंस। विचार सरल था - श्री हंस जी महाराज और उनकी पत्नी श्री राजेश्वरी देवी के जीवन को श्रद्धांजलि देना, जो आध्यात्मिक नेता थे जिन्होंने प्रेम और सार्वभौमिक भाईचारे का संदेश दिया। जब हमने शुरू में चर्चा की कि हम श्री हंस जी के काम को कैसे श्रेय दे सकते हैं और समाज के लिए उनके योगदान में कैसे योगदान दे सकते हैं, तो यह तय हुआ कि परोपकार उन लक्ष्यों को सबसे अच्छी तरह से पूरा करेगा। और इस प्रकार, अप्रैल 2009 में, हमने हंस फाउंडेशन नाम पंजीकृत किया। यह



541Online

आसान हिस्सा था। जैसे ही फाउंडेशन ने अपने पहले कदम उठाए, हमें जल्द ही एहसास हुआ कि हालांकि धर्मार्थ प्रकृति का बचाव और राहत हमेशा काम का एक अनिवार्य हिस्सा होगा, या जैसा कि मेरी माँ इसे 'दिल का काम' कहती हैं, भविष्य की झलक देखना और स्थिरता और स्वतंत्रता के लिए रास्ते बनाना महत्वपूर्ण था, या दूसरे शब्दों में 'दिमाग का काम'। हमने शुरू से ही बड़े सपने देखे। हमने खुद को कभी एक राज्य या क्षेत्र तक सीमित नहीं रखा। हमने जानबूझकर धार्मिक और सांप्रदायिक विभाजन से खुद को दूर रखा। हमारा मूल सिद्धांत पहुंच प्रदान करना और उसे बेहतर बनाना था और आज भी है। हमारे बड़े, खूबसूरत देश में कोई भी व्यक्ति स्वच्छ पानी या अपने बच्चों को स्कूल भेजने के अधिकार से वंचित नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति दवा या डॉक्टरों की कमी से नहीं मरना चाहिए। बच्चों को उनके सपनों को पूरा करने और महान चीजें हासिल करने के लिए उपकरण प्रदान किए जाने चाहिए। विकलांग लोगों के पास समान बुनियादी मानवाधिकार और सपने हैं और उन्हें उन सपनों को साकार करने के लिए समर्थन की आवश्यकता है। भारत के प्रत्येक किसान के पास जीवन में अपने मार्ग को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी और तरीकों तक पहुंच होनी चाहिए। और मैं आज फाउंडेशन को इसी तरह देखता हूँ। कई लोगों के लिए एक साधन। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसे भागीदार हैं जो हमारे



5410online

सपनों में विश्वास करते हैं और हमारी दृष्टि को साझा करते हैं। हमें केंद्र और राज्य सरकारों से द्विदलीय समर्थन मिला है, जो वास्तव में अपने राज्यों के सबसे दूरदराज के इलाकों में लोगों तक पहुंचना चाहते हैं और समझते हैं कि हंस फाउंडेशन उस अंतर को पाटने में मदद कर रहा है। हम हर कदम पर श्री भोले जी और श्री मंगला जी से प्रेरित हुए हैं, जो अथक रूप से हर स्कूल और अस्पताल जाते हैं और मदद मांगने वाले सभी लोगों के लिए अपना दिल खोलते हैं। हम मनोज भार्गव को उनके देश के प्रति समर्पण के लिए धन्यवाद देते हैं और कभी भी 'क्यों' या 'कैसे' के बारे में नहीं पूछते हैं कि हम अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने की योजना बनाते हैं। क्योंकि हम जिन लोगों की मदद करते हैं, उनकी तरह हम भी सपने देखते हैं। हम एक ऐसे देश का सपना देखते हैं जहाँ लड़कियों को कभी भी अपने भविष्य के बारे में दोबारा नहीं सोचना पड़े। हम स्वच्छ नदियों, हरे-भरे जंगलों और माँ प्रकृति के साथ एक प्रेमपूर्ण रिश्ते का सपना देखते हैं। हम स्वस्थ दिमाग और स्वस्थ शरीर के लिए लगातार प्रयास करते हैं जो एक स्वस्थ राष्ट्र के लिए एक साथ आएंगे। प्रत्येक व्यक्ति जिसने फाउंडेशन को अपना समय दिया है, वह इसके साथ बड़ा हुआ है। और जैसे-जैसे हम दशक पूरा करते हैं, मैं एक शानदार टीम के साथ आने वाले वर्षों का इंतजार कर रहा हूँ। जैसा कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कहा, 'सबसे अच्छा अभी बाकी है।'



5410online



स्रोत: हंस फाउंडेशन आधिकारिक वेबसाइट

THF के कार्यक्रम मुख्य रूप से देश के सबसे ग्रामीण और अविकसित क्षेत्रों में लागू किए जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में, THF ने राज्य और केंद्र सरकारों, संस्थानों, कॉर्पोरेट्स, शिक्षाविदों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिलकर पैमाने और अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने के लिए स्थायी हस्तक्षेप के लिए अपनी धर्मार्थ गतिविधियों का विस्तार किया है। फाउंडेशन द्वारा कार्यान्वित किए गए हस्तक्षेप जमीनी स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों तक फैले हुए हैं। फाउंडेशन शिक्षा को एक मुख्य विषयगत क्षेत्र के रूप में काम कर रहा है। हम समझते हैं कि शिक्षा एक मानव अधिकार और एक सार्वजनिक भलाई है जो देश के स्वास्थ्य और भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। हंस फाउंडेशन, सामुदायिक स्तर पर काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से, यह सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है कि



541Online

दूरदराज के क्षेत्रों के बच्चों को सस्ती शिक्षा मिले। THF निरक्षरता और जल्दी पढ़ाई छोड़ने के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक व्यापक-आधारित रणनीति का उपयोग करता है। स्कूलों का समर्थन करने के अलावा, हमारे कार्यक्रम शिक्षा की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जहाँ भी आवश्यक हो, तकनीक पेश कर रहे हैं और सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। THF ने सफल कार्यक्रमों का विस्तार और गति देने और छात्रों की क्षमता को उजागर करने के लिए अभिनव समाधानों की पहचान करने के लिए शिक्षकों, नीति निर्माताओं, अभिभावकों और समुदायों के साथ काम करने वाले संगठनों के साथ भागीदारी की है। हमारे स्कूल कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी छात्र हाई स्कूल पास करें और स्नातक अध्ययन के लिए तैयार हों।



541Online



स्रोत: हंस फाउंडेशन आधिकारिक

वेबसाइट

औपचारिक विद्यालय

देश में विद्यालयों की अपर्याप्त संख्या के अंतर को पाटने के हमारे प्रयास में, THF विभिन्न राज्यों में विद्यालयों के निर्माण में सहायता कर रहा है। ये विद्यालय झुग्गी-झोपड़ियों, वंचित परिवारों, अनाथों, सड़क पर रहने वाले बच्चों और मज़दूरों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं, जिनकी स्कूलों तक तत्काल पहुँच नहीं है। इनमें से कई विद्यालयों में बच्चों के लिए आवासीय सुविधाएँ भी प्रदान की गई हैं।



541Online



स्रोत: हंस फाउंडेशन आधिकारिक वेबसाइट

हील पैराडाइज़ स्कूल - THF पार्टनर

डॉ. सत्य प्रसाद कोनेरू द्वारा स्थापित HEAL (सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा) एक अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी है, जो भारत, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन में पंजीकृत है। इसकी स्थापना भारत में वंचित और बेसहारा बच्चों को आश्रय, सहायता, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। HEAL आंध्र प्रदेश के गुंटूर और हैदराबाद शहर में परित्यक्त/सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए एक आवासीय घर और एक स्कूल चलाता है। वर्तमान में, HEAL भारत में 1,000



541Online

बच्चों की देखभाल करता है। यह भविष्य में 10,000 बच्चों को अपना समर्थन देने की योजना बना रहा है।



स्रोत: हंस फाउंडेशन आधिकारिक वेबसाइट

शोध की पृष्ठभूमि

- **उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है, जहाँ शैक्षिक सुविधाओं का अभाव और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच एक बड़ी चुनौती रही है।**
- **राज्य के सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों की कमी, और संसाधनों की अनुपलब्धता जैसे मुद्दे लंबे समय से चिंता का विषय बने हुए हैं।**



541Online

- पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) मॉडल को शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए एक प्रभावी उपकरण माना गया है।
- हंस फाउंडेशन, एक गैर-लाभकारी संगठन, उत्तराखंड में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए विभिन्न परियोजनाएँ चला रहा है, जिससे विद्यालयी शिक्षा में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं।
- इस शोध के माध्यम से यह जानने की कोशिश की जाएगी कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल और हंस फाउंडेशन की पहल किस हद तक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार ला रहे हैं।

उत्तराखंड की शिक्षा प्रणाली की स्थिति

शिक्षा में सार्वजनिक और निजी सहभागिता

साहित्य की समीक्षा



541Online

सार्वजनिक निजी भागीदारी की परिभाषा

ऐसा लगता है कि सार्वजनिक निजी भागीदारी की कोई उचित और स्पष्ट परिभाषा नहीं है; लेकिन विभिन्न व्याख्याएँ उपलब्ध हैं। हम सार्वजनिक निजी भागीदारी को कुछ शब्दों में परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि इसका दायरा बहुत बड़ा है। सार्वजनिक निजी भागीदारी कार्यक्रमों को अपनाने वाले अधिकांश देशों ने सार्वजनिक निजी भागीदारी की परिभाषा का कोई न कोई रूप प्रदान करने का प्रयास किया है। जैसे-

- ब्राजील का नया सार्वजनिक निजी भागीदारी कानून अपने अनुच्छेद 2 में परिभाषित करता है कि सार्वजनिक निजी भागीदारी अनुबंध सरकार या सार्वजनिक संस्थाओं और निजी संस्थाओं के बीच किए गए समझौते हैं जो सार्वजनिक हित में सेवाओं, उपक्रमों और गतिविधियों को (पूरे या आंशिक रूप से) प्रबंधित करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्व स्थापित करते हैं, जहाँ निजी क्षेत्र वित्तपोषण, निवेश और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है।

- आयरलैंड सार्वजनिक निजी भागीदारी को राज्य प्राधिकरण और निजी भागीदार के बीच राज्य प्राधिकरण के अधिदेश के भीतर कार्य करने के लिए की गई किसी भी व्यवस्था के रूप में



541Online

परिभाषित करता है, और इसमें डिज़ाइन, निर्माण, संचालन और वित्त के विभिन्न संयोजन शामिल होते हैं।

• दक्षिण अफ्रीका में, कानून में सार्वजनिक निजी भागीदारी को एक सरकारी संस्थान और एक निजी पक्ष के बीच एक अनुबंध के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां बाद वाला एक संस्थागत कार्य करता है और/या राज्य की संपत्ति का उपयोग करता है, और जहां परियोजना के बड़े जोखिम तीसरे पक्ष को दिए जाते हैं।

• यूके की निजी वित्त पहल (पीएफआई), जहां सार्वजनिक क्षेत्र लंबी अवधि के अनुबंधों के तहत निजी क्षेत्र से सेवाएं खरीदता है, उस देश के सार्वजनिक निजी भागीदारी कार्यक्रम का सबसे प्रसिद्ध घटक है।

• भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग, 2007 के अनुसार, सार्वजनिक निजी भागीदारी को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, “सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई (प्रायोजक प्राधिकरण) और निजी क्षेत्र की इकाई (एक कानूनी इकाई जिसमें 51% या उससे अधिक इक्विटी निजी भागीदार/भागीदारों के पास है) के बीच एक साझेदारी जो वाणिज्यिक शर्तों पर



5410online

एक निर्दिष्ट अवधि (रियायती अवधि) के लिए सार्वजनिक उद्देश्य के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण और/या प्रबंधन के लिए है और जिसमें निजी भागीदार को एक पारदर्शी और खुली खरीद प्रणाली के माध्यम से खरीदा गया है”।

भारतीय शिक्षा प्रणाली में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के उद्देश्य और लक्ष्य

- भारतीय शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता को ऊपर उठाना।
- छात्रों के नामांकन अनुपात को बढ़ाने में मदद करता है।
- शिक्षा प्रणाली के परिणामों में सुधार करता है।
- सार्वजनिक निजी और सरकारी क्षेत्र के बीच समन्वय बनाए रखना।
- सरकार के बोझ को कम करना।

सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के लाभ

”शिक्षा एक सामाजिक कर्तव्य है और न केवल सरकार की बल्कि नागरिक समाज की भी जिम्मेदारी है। शिक्षा सहित हमारे पूरे समाज के ताने-बाने पर हमारे इतिहास के प्रभाव इतने गहरे



541Online

हैं कि एक मजबूत शिक्षा प्रणाली बनाने के लिए सभी क्षेत्रों के प्रयासों की आवश्यकता होगी,” क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण और शिक्षा संस्थान के लिए अनुसंधान और विकास बारबरा वैलेंटाइन कहते हैं।

सार्वजनिक निजी भागीदारी अच्छा बुनियादी ढांचा प्रदान करता है जो पूरी तरह से निजी या पूरी तरह से सार्वजनिक हो सकता है। प्रत्येक भागीदार वह करता है जो वह सबसे अच्छा करता है।

• सार्वजनिक निजी भागीदारी सार्वजनिक क्षेत्र में पर्याप्त निवेश सुनिश्चित करता है और प्रभावी सार्वजनिक संसाधन प्रबंधन प्रदान करता है;

• सार्वजनिक निजी भागीदारी हर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बहुत तेजी से पूरा करता है, इसलिए वे देरी को कम कर सकते हैं या समय-सीमा को पूरा कर सकते हैं।

• सार्वजनिक निजी भागीदारी का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि 'निवेश पर रिटर्न' या आरओआई पारंपरिक या सरकारी प्रणाली से अधिक है।



शोध उद्देश्य

- उत्तराखंड में विद्यालयी शिक्षा में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) के मॉडल का अध्ययन करना।
- शिक्षा की गुणवत्ता पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का विश्लेषण करना।
- हंस फाउंडेशन द्वारा उत्तराखंड में संचालित शैक्षिक परियोजनाओं की भूमिका और योगदान का मूल्यांकन करना।
- हंस फाउंडेशन की परियोजनाओं के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के सफल और असफल पहलुओं की पहचान करना।
- उत्तराखंड में सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से शैक्षिक सुधारों की संभावनाओं और चुनौतियों का विश्लेषण करना।

हंस फाउंडेशन के कार्यक्रमों का विश्लेषण

हंस फाउंडेशन ने उत्तराखंड में शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न योजनाएँ और कार्यक्रम संचालित किए हैं,

जिनका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना और शिक्षा के प्रति समुदायों में जागरूकता लाना है।



541Online

इनके कार्यक्रमों में शिक्षक प्रशिक्षण, स्कूलों में बुनियादी ढाँचे का विकास, छात्रवृत्ति योजनाएँ, और डिजिटल शिक्षा का विस्तार शामिल है। हंस फाउंडेशन ने सरकारी और निजी स्कूलों में बेहतर संसाधन उपलब्ध कराए हैं, ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।

उत्तराखंड में शिक्षा सुधार में हंस फाउंडेशन की भूमिका का आकलन

उत्तराखंड में शिक्षा सुधार के प्रयासों में हंस फाउंडेशन की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण रही है। फाउंडेशन ने पहाड़ी और ग्रामीण इलाकों में स्कूलों का सुदृढीकरण किया है, जिससे बच्चों की शिक्षा तक पहुँच आसान हुई है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षण के स्तर को सुधारने की दिशा में प्रयास किए गए हैं। हंस फाउंडेशन के इन प्रयासों ने शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई है और छात्रों की स्कूलों में उपस्थिति में भी वृद्धि दर्ज की गई है।

शोध प्रविधि (Methodology)

शोध की प्रविधि में उत्तराखंड के विभिन्न विद्यालयों में हंस फाउंडेशन द्वारा संचालित कार्यक्रमों का गहन अध्ययन किया जाएगा। यह अध्ययन गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों दृष्टिकोणों को



541Online

सम्मिलित करेगा, जिससे शिक्षा में NGO की भूमिका और योगदान का मूल्यांकन किया जा सकेगा।

शोध के लिए चयनित विधियाँ

इस शोध में क्षेत्रीय अध्ययन, सर्वेक्षण और साक्षात्कार विधियों का उपयोग किया जाएगा।

शिक्षकों, छात्रों, और प्रशासनिक अधिकारियों से साक्षात्कार के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जाएगी। इसके अलावा, सरकारी रिपोर्ट्स और हंस फाउंडेशन की उपलब्ध रिपोर्टों का विश्लेषण भी किया जाएगा।

डेटा संग्रहण और विश्लेषण के तरीके

शोध के लिए प्राथमिक और द्वितीयक डेटा का संग्रहण किया जाएगा। प्राथमिक डेटा के लिए शिक्षकों, छात्रों, और अन्य हितधारकों से साक्षात्कार और प्रश्नावली का उपयोग किया जाएगा। द्वितीयक डेटा के लिए शैक्षिक संस्थाओं की रिपोर्ट्स, हंस फाउंडेशन की प्रकाशित सामग्री, और सरकारी शिक्षा रिपोर्ट्स का विश्लेषण किया जाएगा। डेटा को सांख्यिकीय उपकरणों की मदद से विश्लेषित किया जाएगा।



5410online

क्षेत्रीय अध्ययन और सर्वेक्षण

उत्तराखण्ड के विभिन्न जिलों में स्थित स्कूलों का चयन किया जाएगा, जहाँ हंस फाउंडेशन के कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। इन स्कूलों में विद्यार्थियों और शिक्षकों के अनुभवों को संकलित करने के लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण और अध्ययन किए जाएंगे। यह सर्वेक्षण शिक्षा के सुधार और हंस फाउंडेशन की प्रभावशीलता को मापने में सहायक होगा।

विद्यालयी शिक्षा में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका

गैर-सरकारी संगठन (NGOs) विद्यालयी शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ सरकारी शिक्षा प्रणाली पूरी तरह सफल नहीं हो पाती। NGOs शैक्षिक संसाधनों का प्रावधान, शिक्षक प्रशिक्षण, और आधारभूत ढाँचे का विकास करने में सहायक होते हैं। वे शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और सुधार को बढ़ावा देते हैं।

गैर-सरकारी संगठनों की परिभाषा और उद्देश्य

गैर-सरकारी संगठन ऐसे संगठन होते हैं जो लाभ कमाने की प्रवृत्ति से परे, समाज की भलाई के लिए कार्य करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को शिक्षा, स्वास्थ्य, और अन्य



541Online

आवश्यक सेवाएँ प्रदान करना होता है। शिक्षा के क्षेत्र में NGOs का उद्देश्य बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच प्रदान करना और शिक्षा में समानता को बढ़ावा देना है।

शिक्षा के क्षेत्र में इनके द्वारा किए गए प्रमुख योगदान

NGOs ने शिक्षा के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय योगदान दिए हैं। इनमें विद्यालयों के बुनियादी ढाँचे का विकास, शिक्षकों का प्रशिक्षण, बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना, और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना शामिल है। इसके अलावा, NGOs शिक्षा में नवीनतम तकनीकों और शैक्षिक सामग्री को छात्रों तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभाते हैं।

उत्तराखंड में हंस फाउंडेशन का योगदान

उत्तराखंड में हंस फाउंडेशन ने शिक्षा सुधार के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने, विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने, और शिक्षा के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएँ चलाई हैं। फाउंडेशन ने विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा और गरीब परिवारों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया है।



हंस फाउंडेशन के प्रमुख कार्यक्रम

हंस फाउंडेशन के प्रमुख कार्यक्रमों में शिक्षक प्रशिक्षण, स्कूलों के लिए डिजिटल शिक्षा की सुविधाएँ, और ग्रामीण इलाकों में स्कूली बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ शामिल हैं। फाउंडेशन ने स्कूलों में आधारभूत टाँचागत विकास पर भी काम किया है, जैसे शौचालय निर्माण, कक्षाओं का पुनर्निर्माण, और पुस्तकालयों की स्थापना।

शिक्षा सुधार के क्षेत्र में हंस फाउंडेशन की पहल

हंस फाउंडेशन ने उत्तराखंड में शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनमें से प्रमुख हैं: डिजिटल शिक्षा के लिए स्मार्ट क्लासरूम का निर्माण, शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम, और छात्रवृत्ति योजनाएँ। इन पहलों ने छात्रों को आधुनिक शिक्षा के साधनों से जोड़ने और शिक्षकों के शिक्षण कौशल को सुधारने में मदद की है।

हंस फाउंडेशन द्वारा संचालित योजनाओं का विश्लेषण

हंस फाउंडेशन द्वारा संचालित योजनाओं में "शिक्षक प्रशिक्षण", "डिजिटल शिक्षा", और "शैक्षिक संसाधन उपलब्धता" शामिल हैं। इन योजनाओं का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि



541Online

फाउंडेशन ने शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार और छात्रों की समग्र शैक्षिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी ढंग से काम किया है।

हंस फाउंडेशन के कार्यक्रमों का प्रभाव

हंस फाउंडेशन के कार्यक्रमों का उत्तराखंड में विद्यालयी शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

इनके माध्यम से स्कूलों में नामांकन दर बढ़ी है, छात्रों की उपस्थिति में सुधार हुआ है, और

शिक्षकों का शिक्षण कौशल बेहतर हुआ है। बालिका शिक्षा को भी विशेष प्रोत्साहन मिला है।

विद्यालयी शिक्षा में गुणवत्ता सुधार

हंस फाउंडेशन के प्रयासों के कारण विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। फाउंडेशन ने

शिक्षकों को नवीनतम शिक्षण विधियों से प्रशिक्षित किया है, जिससे शिक्षण का स्तर बेहतर

हुआ है। इसके अलावा, छात्रों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक सामग्री और उपकरण भी

उपलब्ध कराए गए हैं।

शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता और वितरण

हंस फाउंडेशन ने स्कूलों में शैक्षिक संसाधनों, जैसे पुस्तकें, विज्ञान प्रयोगशाला उपकरण, और



541Online

डिजिटल शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराए हैं। इन संसाधनों का वितरण राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में भी किया गया है, जहाँ सरकारी व्यवस्था की पहुँच सीमित होती है।

लाभार्थियों की प्रतिक्रिया

हंस फाउंडेशन के कार्यक्रमों से लाभान्वित छात्रों और शिक्षकों ने फाउंडेशन के प्रयासों की सराहना की है। छात्रों ने बताया कि स्कूलों में उपलब्ध नई सुविधाओं और शिक्षण सामग्री से उनकी शिक्षा में रुचि बढ़ी है। शिक्षकों ने भी कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों से उनके शिक्षण कौशल में सुधार हुआ है और वे अब अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ा पा रहे हैं।

चुनौतियाँ और सीमाएँ

शिक्षा क्षेत्र में गैर सरकारी संगठन के लिए कुछ चुनौतियाँ हैं, क्योंकि उन्हें अंतर-भरने वाले के रूप में देखा जाता है, जैसे कि वित्त पोषण की कमी, पारदर्शिता, तथा "गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की भर्ती, प्रशिक्षण और उन्हें बनाए रखने" की आवश्यकता। वित्तीय संसाधनों या निधियों की कमी एक बड़ी समस्या है, साथ ही शैक्षिक क्षेत्र में कठोरता भी है, जो गैर सरकारी संगठन के काम और मॉडल में बाधा डालती है। धन जुटाने वाले पेशेवरों की कमी है और वे आमतौर पर क्षेत्र में कुछ



541Online

साल बिताने के बाद अंतर्राष्ट्रीय सहायता निकायों या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ काम करने लगते हैं। जहाँ ऐसा हुआ है, वहाँ गैर सरकारी संगठन को ऐसे संबंध बनाने और मुख्यधारा की सरकारी स्कूल प्रणाली में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के महत्व पर जोर देने के लिए काफी प्रयास करने पड़े हैं। फिर भी, राज्यों को ऐसे संबंध स्थापित करने के लिए अधिक राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। इससे भी बदतर, राज्य स्तर पर राजनीतिक शासन में परिवर्तन ऐसी साझेदारी को खतरे में डाल सकता है। इन संबंधों की कमज़ोरी और शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता को मुख्यधारा में लाने के लिए विशेष व्यक्तियों पर निर्भरता, सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए अधिक सामान्य राजनीतिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता को उजागर करती है। अगस्त्य फाउंडेशन के हस्तक्षेप में देखी गई एक विशिष्ट सीमा प्रयोगशाला और प्रयोगों के माध्यम से पढ़ाए गए विज्ञान अवधारणाओं को समझने की छात्रों की क्षमता थी, जिसे छात्र समझ नहीं पाए क्योंकि उनके पास अवधारणाओं की समझ की कमी थी।

शिक्षा क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ



1. भौगोलिक बाधाएँ

उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, जहाँ गाँव और विद्यालय दूर-दूर और दुर्गम स्थानों पर स्थित हैं। इन क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियाँ, जैसे ऊँचे पहाड़, खराब सड़कें, और प्राकृतिक आपदाएँ (बाढ़, भूस्खलन), NGO के लिए शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों का सुचारू रूप से संचालन करना कठिन बना देती हैं। कई बार शिक्षकों और संसाधनों को इन क्षेत्रों तक पहुँचाने में भी कठिनाइयाँ होती हैं।

2. अल्प आधारभूत संरचना

कई ग्रामीण इलाकों में स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं, जैसे पर्याप्त कक्षाएँ, पीने का पानी, शौचालय, और बिजली की कमी है। इन आधारभूत टांचागत समस्याओं के कारण NGO के शिक्षा सुधार के प्रयास प्रभावी रूप से कार्यान्वित नहीं हो पाते।

3. स्थानीय समुदाय में जागरूकता की कमी

उत्तराखंड के कई ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता की कमी देखने को मिलती है। माता-पिता अक्सर बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय घरेलू कार्यों या कृषि में शामिल कर लेते



541Online

हैं। NGO को समुदाय को शिक्षा के लाभ समझाने और उनकी मानसिकता बदलने में कठिनाइयाँ होती हैं।

हंस फाउंडेशन के कार्यान्वयन की चुनौतियाँ

1. सुव्यवस्थित वितरण तंत्र की कमी

हंस फाउंडेशन ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक कार्यक्रम चलाए हैं, लेकिन दुर्गम इलाकों में आवश्यक संसाधनों और सुविधाओं का सुव्यवस्थित वितरण करना चुनौतीपूर्ण साबित होता है। कई बार सामग्री और उपकरण दूरस्थ स्कूलों तक पहुँचाने में देरी हो जाती है, जिससे कार्यक्रम समय पर लागू नहीं हो पाते।

2. स्थानीय प्रशासन के साथ तालमेल

कई बार हंस फाउंडेशन को स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जटिलता और निर्णय लेने में देरी के कारण फाउंडेशन के कार्यक्रमों का समय पर क्रियान्वयन नहीं हो पाता। इसके अलावा, कभी-कभी योजनाओं के लिए आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने में भी कठिनाइयाँ आती हैं।



541Online

3. स्थानीय भाषा और सांस्कृतिक चुनौतियाँ

उत्तराखण्ड के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न बोलियाँ और संस्कृतियाँ विद्यमान हैं। हंस फाउंडेशन को स्थानीय समुदाय के साथ काम करते समय भाषा और सांस्कृतिक अंतर का सामना करना पड़ता है, जिससे शिक्षा संबंधी संदेश को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

उत्तराखण्ड में विद्यालयी शिक्षा सुधार के लिए हंस फाउंडेशन द्वारा संचालित प्रमुख कार्यक्रमों का विश्लेषण (माध्यमिक डेटा आधारित)

तालिका: उत्तराखण्ड में विद्यालयी शिक्षा सुधार के लिए हंस फाउंडेशन द्वारा संचालित प्रमुख कार्यक्रमों का विश्लेषण (माध्यमिक डेटा आधारित)

क्रमांक	कार्यक्रम का नाम	प्रारंभ वर्ष	लक्ष्य समूह	उद्देश्य	परिणाम/प्रभाव	डेटा स्रोत
---------	------------------	--------------	-------------	----------	---------------	------------



5410online

1	शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम	2015	सरकारी और निजी विद्यालयों के शिक्षक	शिक्षकों की शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार लाना	500+ शिक्षकों का प्रशिक्षण; शिक्षण गुणवत्ता में सुधार	हंस फाउंडेशन की वार्षिक रिपोर्ट, 2020
2	स्मार्ट क्लासरूम पहल	2017	ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्र के विद्यालय	डिजिटल शिक्षा का प्रसार करना	100+ विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना	राज्य शिक्षा विभाग की रिपोर्ट, 2021



5410online

3	छात्रवृत्ति योजना	2016	बंधित और आर्थिक रूप से कमजोर छात्र	आर्थिक सहायता प्रदान करना	2000+ छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान	हंस फाउंडेशन की छात्रवृत्ति योजना रिपोर्ट, 2022
4	स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास	2014	ग्रामीण विद्यालय	विद्यालयों की आधारभूत संरचना सुधारना	50+ विद्यालयों में शौचालय और कक्षाओं का निर्माण	राज्य बुनियादी ढांचा विकास रिपोर्ट, 2020



5410online

5	बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना	2018	ग्रामीण और वंचित बालिकाएँ	बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना	1000+ बालिकाओं को शिक्षा में शामिल किया गया	उत्तराखंड राज्य शिक्षा रिपोर्ट, 2021
6	स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रम	2015	ग्रामीण विद्यालयों के छात्र	छात्रों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार	10,000+ छात्रों को स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान	हंस फाउंडेशन की स्वास्थ्य सेवा रिपोर्ट, 2019

स्रोत: स्व-निर्मित

डेटा विश्लेषण के लिए संभावित संकेत



541Online

1. **शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम से जुड़े शिक्षक के प्रदर्शन और विद्यार्थियों के शैक्षिक परिणामों में सुधार की समीक्षा।
2. **स्मार्ट क्लासरूम पहल:** डिजिटल शिक्षा के प्रभाव का मूल्यांकन, विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में।
3. **छात्रवृत्ति योजना:** छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की शैक्षिक प्रगति की तुलना।
4. **इंफ्रास्ट्रक्चर विकास:** विद्यालयों में शौचालय और कक्षाओं की उपलब्धता के बाद छात्रों की उपस्थिति में परिवर्तन का विश्लेषण।
5. **बालिका शिक्षा प्रोत्साहन:** बालिका नामांकन दर और शैक्षिक प्रगति पर इसका प्रभाव।
6. **स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रम:** स्वास्थ्य सेवाओं के परिणामस्वरूप शैक्षिक प्रदर्शन और स्कूल में उपस्थिति का आकलन।

विश्लेषण



541Online

उत्तराखंड के संदर्भ में विद्यालयी शिक्षा की स्थिति का आकलन करते हुए, यह देखा गया है कि राज्य की भौगोलिक कठिनाइयाँ, सीमित संसाधन, और सरकारी तंत्र की सीमाओं के चलते शिक्षा क्षेत्र में सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है। इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन संगठनों ने जहाँ सरकार की सीमाओं को पूरा करने का प्रयास किया, वहीं शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, आधारभूत संरचना का विकास, और शिक्षा तक पहुँच को व्यापक रूप से बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए।

1. गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका का विश्लेषण

गैर-सरकारी संगठन शिक्षा में सरकारी प्रयासों के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। ये संगठन विशेष रूप से उन दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा को पहुँचाने का काम करते हैं, जहाँ सरकारी पहुँच कठिन होती है। उत्तराखंड के ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों में NGOs ने स्कूलों के बुनियादी ढाँचे में सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण, और छात्रों को शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराने में अहम योगदान दिया है। इसके अलावा, NGOs ने शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और बच्चों को स्कूलों में बनाए रखने के लिए समुदायों के साथ काम किया है।



2. हंस फाउंडेशन की भूमिका का विश्लेषण

उत्तराखण्ड में शिक्षा सुधार की दिशा में हंस फाउंडेशन की भूमिका को देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि फाउंडेशन ने विशेष रूप से शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने, शैक्षिक सुविधाओं को उन्नत करने, और गुणवत्ता सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हंस फाउंडेशन ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है, जिसमें शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और स्मार्ट क्लासरूम जैसी तकनीकी शिक्षा की सुविधा को प्राथमिकता दी गई है। इन पहलों के परिणामस्वरूप, कई स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति और प्रदर्शन में सुधार हुआ है।

3. हंस फाउंडेशन के कार्यक्रमों का प्रभाव

फाउंडेशन द्वारा संचालित कार्यक्रमों का विद्यालयों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कारण शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, और वे अब अधिक कुशल और प्रेरित होकर पढ़ा रहे हैं। स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल सामग्री के माध्यम से छात्रों की सीखने की क्षमता बढ़ी है। इसके साथ ही, फाउंडेशन ने कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और आर्थिक सहायता भी प्रदान की, जिससे शिक्षा में समानता बढ़ी है।



5410online

4. चुनौतियों का विश्लेषण

हालाँकि हंस फाउंडेशन और अन्य NGOs ने शिक्षा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुधार किए हैं, फिर भी कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं। उत्तराखंड की दुर्गम भौगोलिक स्थिति, आधारभूत संरचना की कमी, और शिक्षकों की सीमित संख्या जैसी समस्याएँ अभी भी मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार और NGO के बीच समन्वय की कमी, समय पर संसाधनों की उपलब्धता में देरी, और सांस्कृतिक विविधता के कारण स्थानीय समुदायों के साथ जुड़ाव की कठिनाइयाँ भी इन संगठनों के कार्यान्वयन को प्रभावित करती हैं।

5. हंस फाउंडेशन के प्रयासों का समग्र मूल्यांकन

हंस फाउंडेशन के प्रयासों का समग्र मूल्यांकन किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने शिक्षा सुधार की दिशा में कई अहम कदम उठाए हैं। उनके कार्यक्रमों ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है, छात्रों की शैक्षिक प्रगति को बढ़ावा दिया है, और शिक्षकों को नवीनतम शिक्षण विधियों से सुसज्जित किया है। हालाँकि, इन पहलों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए स्थायी संसाधन और सरकारी तंत्र के साथ बेहतर समन्वय आवश्यक है।



541Online

जीवन कौशल विकास:

1. परियोजना लड़कियों में आवश्यक जीवन कौशल विकसित करने पर केंद्रित है। जीवन कौशल शिक्षा सत्रों के माध्यम से, लड़कियाँ निर्णय लेने, प्रभावी संचार, सार्वजनिक भाषण और उच्च शिक्षा के लिए परिवार के साथ बातचीत जैसी मुख्य योग्यताएँ सीखती और प्रदर्शित करती हैं।
2. ये कौशल उनके व्यक्तिगत विकास और भविष्य की सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं।

सहयोग और हितधारक जुड़ाव:

1. परियोजना अपने प्रभाव को अधिकतम करने के लिए सरकार और अन्य गैर सरकारी संगठनों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करती है। साझेदारी के माध्यम से, परियोजना अधिक संख्या में लड़कियों तक पहुँचने और प्रयासों के दोहराव से बचने के लिए संसाधनों, विशेषज्ञता और नेटवर्क का लाभ उठाती है।
2. माता-पिता, समुदाय, स्कूल और सरकारी अधिकारियों सहित हितधारक जुड़ाव परियोजना की सफलता में एक महत्वपूर्ण कारक हैं।

ड्रॉपआउट दरों में कमी:



541Online

1. परियोजना ने लड़कियों के बीच ड्रॉपआउट दरों को सफलतापूर्वक कम किया है। शैक्षणिक सहायता, जीवन कौशल शिक्षा और कैरियर मार्गदर्शन प्रदान करके, परियोजना एक सहायक वातावरण बनाती है जो लड़कियों को स्कूल में रहने और अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

कैरियर मार्गदर्शन में भागीदारी में वृद्धि:

1. परियोजना लड़कियों को कैरियर मार्गदर्शन गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल करती है। परिणामस्वरूप, लड़कियों का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत इन सत्रों में भाग लेता है, जिससे उन्हें विभिन्न कैरियर अवसरों के बारे में मूल्यवान जानकारी मिलती है।
2. इससे उन्हें अपनी भविष्य की शिक्षा और कैरियर पथ के बारे में सूचित निर्णय लेने का अधिकार मिला है।

निष्कर्ष

हंस फाउंडेशन ने उत्तराखंड में शिक्षा सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनमें स्मार्ट क्लासरूम, शिक्षक प्रशिक्षण, और छात्रवृत्ति कार्यक्रम शामिल हैं। फाउंडेशन के प्रयासों ने न



541Online

केवल छात्रों को बेहतर शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराए हैं, बल्कि शिक्षकों को भी अधिक सक्षम और प्रशिक्षित बनाया है। इसके साथ ही, हंस फाउंडेशन ने बालिकाओं और वंचित वर्गों के बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए, जिससे शिक्षा में समानता और समावेशिता बढ़ी है।

हालाँकि हंस फाउंडेशन और अन्य NGOs ने शिक्षा सुधार की दिशा में सकारात्मक प्रभाव डाला है, फिर भी कुछ चुनौतियाँ बरकरार हैं। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियाँ, आधारभूत संरचना की कमी, और सरकारी तंत्र के साथ समन्वय में कठिनाई जैसे मुद्दे अभी भी प्रभावशाली कार्यान्वयन में बाधक हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार और NGO के बीच बेहतर तालमेल और दीर्घकालिक योजनाओं की आवश्यकता है।

उत्तराखंड में शिक्षा सुधार की दिशा में हंस फाउंडेशन और अन्य NGOs के प्रयासों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि इन संगठनों ने शिक्षा में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है। इन संगठनों ने न केवल बच्चों के लिए बेहतर शैक्षिक सुविधाएँ उपलब्ध कराईं, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता और पहुँच को भी व्यापक रूप से बढ़ाया है। हालाँकि, अधिक प्रभावी और स्थायी सुधार के लिए आवश्यक है कि NGOs के प्रयासों को सरकार और स्थानीय समुदायों के सहयोग से और



541Online

अधिक सुदृढ़ किया जाए। इस प्रकार, उत्तराखंड के विद्यालयी शिक्षा में NGOs की भूमिका आने वाले समय में और अधिक महत्वपूर्ण होती जाएगी, जिससे राज्य के दूरस्थ और वंचित इलाकों में शिक्षा का स्तर और बेहतर हो सके।

सन्दर्भ सूची

1. AICTE (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद)। 1994. तकनीकी शिक्षा के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए उच्च-शक्ति समिति की रिपोर्ट (स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट)। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
2. ब्लागोस्कू, मोनिका और जॉन यंग। 2005. भागीदारी और जवाबदेही: नागरिक समाज संगठनों का समर्थन करने वाली एजेंसियों के बीच वर्तमान सोच और दृष्टिकोण। लंदन: ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट।
3. बोक, डेरेक। 2004. बाजार में विश्वविद्यालय: उच्च शिक्षा का व्यावसायीकरण। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस।



541Online

4. क्यूब्स, एंटोनियो गार्सिया। 1893. मेक्सिको: इसका व्यापार, उद्योग और संसाधन। (फुलर, ब्रूस एट अल. 1986 में उद्धृत। शिक्षा कब आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है? मेक्सिको में स्कूल विस्तार और स्कूल की गुणवत्ता, शिक्षा का समाजशास्त्र 59 (3) (जुलाई): 167-81.
5. ड्रैक्सलर, एलेक्जेंड्रा. 2012. शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक-निजी भागीदारी: नई क्षमता या सार्वजनिक वस्तुओं का निजीकरण। शिक्षा में सार्वजनिक निजी भागीदारी में (एस.एल. रॉबर्टसन एट., संपादक), चेल्टेनहैम: एडवर्ड एल्गार, पृष्ठ 43-62
6. इवांस, जी.आर., और डी.ई. पैकहम. 2003. विश्वविद्यालय-उद्योग इंटरफेस में नैतिक मुद्दे: आगे का रास्ता? विज्ञान और इंजीनियरिंग नैतिकता 9 (1) (जनवरी): 3-16.
7. गेराई, जेसिका. 2015. नवउदारवादी समय में सार्वजनिक शिक्षा: स्मृति और इच्छा, शिक्षा नीति की पत्रिका 30 (6): 855-68.
8. गिन्सबर्ग, मार्क. 2012. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, नवउदारवादी वैश्वीकरण और लोकतंत्रीकरण. शिक्षा में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (एस.एल. रॉबर्टसन एट., संपादक), चेल्टेनहैम: एडवर्ड एल्गार, पृष्ठ 63-78
9. गोपालन, प्रीथा. 2013. सार्वजनिक-निजी भागीदारी विरोधाभास. नई दिल्ली: सेज.



541Online

कुमार, कृष्णा. 2008. शिक्षा में भागीदार, आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक 43 (3) (जनवरी

19): 8-11

10. मुरलीधरन, कार्तिक. 2006. सार्वभौमिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सार्वजनिक-निजी

भागीदारी, सेमिनार. संख्या 565 (सितंबर): 15 उपलब्ध:

http://www.indiaseminar.com/2006/565/565_karthik_muralidharan.htm योजना

आयोग. 2008. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (सार्वजनिक-निजी

भागीदारी) पर मसौदा परामर्श पत्र। नई दिल्ली: योजना आयोग।

11. रॉबर्टसन, एस.एल., और एंटोनी वर्गर 2012. सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से शिक्षा

का संचालन। शिक्षा में सार्वजनिक निजी भागीदारी (एस.एल. रॉबर्टसन एट., सं.), चेल्सेनहैम:

एडवर्ड एल्गर, पृ. 21-42